नईदुनिया



## सत्ता के 'सेकेंड फ्लोर' पर 18 महीने से लटका है ताला, क्या 23 नवंबर से पहले खुलेगा?

डॉ. शिशिर उपाध्याय

भोपाल। मध्य प्रदेश में मंत्री बनना सत्ता की पहली मंजिल है, लेकिन निगम-मंडलों में चेयरमैन बनना दूसरी मंजिल। इस दूसरी मंजिल पर पिछले डेढ़ साल से ताला लगा है। करीब डेढ़ दर्जन निगम, मंडल, प्राधिकरण और बोर्ड में अब तक राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई हैं। कुर्सियां खाली हैं और करीब 150 नेताओं का राजनीतिक भविष्य इन नियुक्तियों पर टिका है।

अब इस ताले के खुलने की उम्मीद बढ़ी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 23 नवंबर को यूके और जर्मनी की इन्वेस्टर्स मीट यात्रा पर जा रहे हैं। चर्चा है कि विदेश रवाना होने से पहले वे कुछ प्रमुख निगम-मंडलों में नियुक्तियों की सूची जारी कर सकते हैं। बाकी 100 से ज्यादा नामों की सूची भाजपा संगठन को सौंपे जाने की तैयारी है, ताकि मुख्यमंत्री की वापसी तक संगठन उन पर मंथन कर सके और अंतिम निर्णय लिया जा सके।

**विदेश उड़ान से पहले सीएम के बैग में होंगी दो लिस्ट, एक जेब में, दूसरी संगठन की टेबल पर**

खाली पदों में भोपाल, इंदौर, कटनी, बुंदेलखंड और महाकौशल विकास प्राधिकरण जैसे महत्वपूर्ण संस्थान शामिल हैं। इनके अलावा राज्य योजना आयोग, सफाई कर्मचारी आयोग, वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग, कृषक आयोग और राज्य कोल जनजाति विकास प्राधिकरण में भी नियुक्तियां होनी हैं। मदरसा बोर्ड, असंगठित कामगार बोर्ड, समाज कल्याण बोर्ड, राज्य हज कमेटी और व्यापार संवर्धन बोर्ड सहित कई संस्थाओं में भी राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार है। इनमें कुछ ऐसे निगम और संस्थान भी हैं, जिनका सीधा संबंध आर्थिक गतिविधियों और महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसलों से है।

### 150 कुर्सियां, 1500 दावेदार, पेंच कहां फंसा है?

इन संस्थाओं में करीब 150 नेताओं को समायोजित किया जाना है, जबकि दावेदारों की संख्या 1500 के आसपास बताई जा रही है। हर विधायक और सांसद अपने पसंदीदा नाम आगे बढ़ा रहा है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, असली पेंच दावेदारों की संख्या और नेताओं की लॉबिंग में फंसा है। पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल के साथ बंद कमरे में करीब दो घंटे तक चर्चा की। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर तिवारी से भी मंथन हुआ। केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने नियुक्तियों में और देरी नहीं करने का मन बनाया है।

### भाजपा संगठन में भी वैकेंसी ही वैकेंसी

सरकार की तरह भाजपा संगठन में भी नियुक्तियों का काम अधूरा है। नए प्रदेश प्रभारी के आने और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर तिवारी के अक्टूबर तक सभी नियुक्तियां पूरी करने के आश्वासन के बावजूद कई जिलों में मोर्चों और प्रकोष्ठों की टीमें गठित नहीं हो पाई हैं।

प्रदेश संगठन की ओर से कई बार जिलों से नाम मांगे गए, लेकिन जिलाध्यक्षों ने सूचियां नहीं भेजीं। अंदरखाने की चर्चा है कि जिलाध्यक्ष, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि अपनी-अपनी पसंद के नामों पर अड़े हुए हैं। किसान मोर्चा और युवा मोर्चा जैसे महत्वपूर्ण मोर्चों की टीमें भी अब तक अधर में हैं।

अब सबकी नजर 23 नवंबर पर है। सवाल यही है कि क्या विदेश रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री सत्ता की दूसरी मंजिल का ताला खोलेंगे या फिर नियुक्तियों का इंतजार और लंबा खिंचेगा?

**गांधी सागर को मिलेगा इंटरनेशनल लुक**

# चंबल की लहरों पर पर्यटन की नई उड़ान

अभय धर्मे, गांधीसागर बाँध

**मुख्यमंत्री ने मंदसौर में 40.50 करोड़ के 5 इको-टूरिज्म प्रोजेक्ट्स का किया भूमिपूजन, बोले - पानी की एक बूंद भी बेकार नहीं जाएगी**



मध्यप्रदेश के पर्यटन मानचित्र पर गांधी सागर अब केवल एक डैम नहीं, बल्कि देश का सबसे बड़ा इको-टूरिज्म हब बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मंदसौर जिले के गांधी सागर में आस्था, ऊर्जा और पर्यटन के संगम के बीच मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के निवेश संवर्धन कार्यक्रम के तहत 40.50 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होने वाली 5 इको-टूरिज्म परियोजनाओं का भूमिपूजन किया।

यह भूमिपूजन ऐसे समय में हुआ जब पूरी कैबिनेट गांधी सागर के बैकवाटर में मौजूद थी। सरकार की यह 9वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक थी, जिसका संदेश साफ है – विकास अब केवल वल्लभ भवन से नहीं, बल्कि प्रदेश के कोने-कोने से तय होगा।

### सुबह चंबल सफारी, शाम को चंबल आरती

दिन की शुरुआत मुख्यमंत्री ने कैबिनेट सहयोगियों के साथ चंबल सफारी से की। टेंट सिटी से गांधी सागर जलाशय के घने जंगलों और तटीय क्षेत्रों तक बोट सफारी का आनंद लिया। वन अधिकारियों से अभयारण्य में चल रहे विकास कार्यों, चीतों के पुनर्वास की तैयारियों और पर्यटन सुविधाओं पर चर्चा की। इसके बाद हिंगलाज रिसॉर्ट बोट क्लब से मिनी क्रूज में सवार होकर मुख्यमंत्री टेंट सिटी बोट क्लब तक पहुंचे। शाम को 21 पुजारियों, मुख्य पुजारी कैलाश भट्ट और बटुकों द्वारा विधि-विधान से मां चंबल की महाआरती की गई। शंखनाद, दीपों की रोशनी और जयकारों के बीच मुख्यमंत्री ने प्रदेश की निरंतर उन्नति और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा – चंबल के बिना यमुना की धारा अधूरी है, यहां घड़ियाल और डॉल्फिन का होना इस नदी की पवित्रता और समृद्धि का प्रमाण है।

### बिजली उत्पादन में 20 गुना छलांग - एक बूंद भी बेकार नहीं

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर गांधी सागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का भी जिक्र किया, जिसे सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा – गांधी सागर डैम का निर्माण आजादी के तुरंत बाद हुआ था। अब हमारी सरकार इस जलराशि का बेहतर उपयोग करने के लिए पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज की नई तकनीक पर काम कर रही है। इससे बिजली का उत्पादन 20 गुना ज्यादा बढ़ेगा। पानी की एक बूंद भी बेकार नहीं जाएगी। दो जलाशय पानी के उसी स्टोरेज से बार-बार बिजली बनाएंगे। बताया जा रहा है कि इस परियोजना के तहत 11,500 करोड़ रुपये की लागत से 1920 से 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है, जो पीक ऑवर्स में प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगी। यह प्रोजेक्ट देश के लिए केस स्टडी बनेगा।

### पम्प्ड हाइड्रो परियोजना की पहली इकाई शुरू

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को गांधी सागर में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नीमच जिले के रामपुर स्थित ग्रीनको पावर प्लांट का अवलोकन किया। उन्होंने पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना की नौ इकाइयों में से एक का बटन दबाकर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना बिजली उत्पादन के क्षेत्र में नई तकनीक और क्रांतिकारी परिवर्तन का माध्यम बनेगी। इसकी कुल लागत 11 हजार 474 करोड़ रुपये है। परियोजना शुरू होने के बाद बिजली की अधिक मांग वाले समय में 2000 मेगावाट तक बिजली उपलब्ध हो सकेगी। इससे प्रदेश में चौबीसों घंटे बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

### उपज से उद्यम तक - किसानों से सीधा संवाद

पर्यटन के साथ-साथ मुख्यमंत्री ने गांधी सागर में 'उपज से उद्यम' प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। यहां मंदसौर-नीमच के किसानों, अफीम उत्पादकों और उद्यमियों ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा गांधी सागर को प्रदेश के प्रमुख इको-टूरिज्म केंद्र के रूप में स्थापित करने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने नीमच जिले के मनासा में 272 करोड़ रुपये से अधिक के 111 से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया।



### 40.50 करोड़ के 5 प्रोजेक्ट्स में क्या-क्या बनेगा

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार इन 5 परियोजनाओं से गांधी सागर क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं का पूरी तरह कायाकल्प होगा:

**टैंट सिटी का विस्तार और अपग्रेडेशन:** लग्जरी टेंट, फाइव स्टार सुविधाओं के साथ रात्रि पर्यटन को बढ़ावा।

**हिंगलाज रिसॉर्ट और बोट क्लब का आधुनिकीकरण:** क्रूज, हाउस बोट और वाटर स्पोर्ट्स की विश्वस्तरीय सुविधा।

**चंबल रिवर क्रूज और सफारी ट्रेल:** घड़ियाल सेंचुरी और डॉल्फिन पॉइंट तक इको-फ्रेंडली सफारी।

**एडवेंचर और इको ट्रेल पार्क:** ट्रेकिंग, बर्ड वॉचिंग, केज कल्चर फिशरीज का अनुभव।

**पर्यटक सुविधा केंद्र और इंटरप्रिटेशन सेंटर:** जहां गांधी सागर बांध के इतिहास से लेकर चंबल के इको सिस्टम तक की जानकारी मिलेगी।

इन परियोजनाओं से क्षेत्र में न केवल पर्यटन सुविधाओं का विस्तार होगा बल्कि इको-टूरिज्म को नई गति मिलेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के सैकड़ों अवसर खुलेंगे।

### क्यों खास है गांधी सागर?

चंबल नदी पर बना गांधी सागर बांध देश के सबसे पुराने और बड़े जलाशयों में से एक है। यह मध्यप्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। यहां घड़ियाल अभयारण्य, हजारों प्रवासी पक्षी, और अब चीता सफारी की संभावनाएं इसे मध्यप्रदेश का स्विट्जरलैंड बनाती हैं। सरकार का लक्ष्य है कि जिस तरह केरल में बैकवाटर टूरिज्म और गुजरात में टेंट सिटी प्रसिद्ध है, उसी तरह गांधी सागर को भारत का नया इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने अंत में कहा – सरकार के तीन साल पूरे होने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि गांधी सागर से मध्यप्रदेश के विकास को नई उड़ान मिले।



**27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण सहित 14 मांगों को लेकर...**

## सपा का प्रदर्शन, वाटर कैनन चलाने से कई घायल

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल:** मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण, किसानों की समस्याओं, आदिवासियों के जल-जंगल-जमीन के अधिकार, महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं को रोजगार सहित विभिन्न मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी ने बुधवार को भोपाल में प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनोज यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ता मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री के निवास का घेराव करने निकले। तरण पुष्कर चौराहे पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। इस दौरान वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए।



प्रदर्शन में ओबीसी विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति की 14 लंबित छात्रवृत्तियों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। जय मूवमेंट ओबीसी के संस्थापक लखपत गुर्जर के अनुसार, वर्ष 2025-26 की योजना में 50 छात्रवृत्तियों का प्रावधान है, लेकिन 14 पात्र विद्यार्थियों को अब तक लाभ नहीं मिला है। संगठन ने पहले लंबित छात्रवृत्तियां जारी करने की मांग की।

प्रदर्शनकारियों ने पीएम-यशस्वी योजना में 25 प्रतिशत वेटेज समाप्त कर सभी पात्र विद्यार्थियों को समान अवसर देने और छात्रवृत्ति चयन प्रक्रिया की जांच कराने की मांग भी की। किसानों के लिए पर्याप्त खाद, फसलों का उचित समर्थन मूल्य और कालाबाजारी रोकने की मांग उठाई गई। आदिवासी परिवारों के वन अधिकारों की रक्षा, अवैध कब्जों और विस्थापन पर रोक लगाने की मांग भी की गई।

## टेलीकॉम विनिर्माण क्षेत्र में 3600 करोड़ का निवेश, 15 हजार रोजगार के अवसर

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल:** मध्यप्रदेश को देश के प्रमुख दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में 19 नवंबर को होटल ताज लेकफ्रंट में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की निवेशक बैठक आयोजित होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इसका शुभारंभ करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री 25 कंपनियों को निवेश के लिए आशय पत्र वितरित करेंगे। इन कंपनियों की ओर से 3600 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावित हैं। इससे 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। इसके साथ ही ग्वालियर में लगभग 450 एकड़ क्षेत्र में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के दूसरे चरण का शुभारंभ भी प्रस्तावित है।

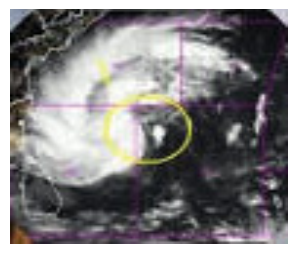
निवेश करने वाली कंपनियों में वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, तेजस नेटवर्क्स, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी और ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स सहित 25 कंपनियां शामिल हैं। बैठक में दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्किंग और संबंधित विनिर्माण क्षेत्रों के निवेशक तथा उद्योग संगठन भी शामिल होंगे।

## अकवान का असर, दो दिन बाद भोपाल इंदौर सहित कई शहरों में वर्षा के आसार

### आज से छाने लगेंगे बादल

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल:** बंगाल की खाड़ी में दक्षिण और उससे लगी पश्चिम-मध्य क्षेत्र में भीषण चक्रवाती तूफान अकवान सक्रिय है। जो उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक इसके शुक्रवार दोपहर के आसपास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के मध्य टकराने के आसार हैं। इसके असर से गुरुवार से मध्य प्रदेश में बादल छाने लगेंगे। साथ ही 21-22 नवंबर को रीवा, जबलपुर, शहडोल, भोपाल, नर्मदापुरम एवं इंदौर संभाग में कहीं-कहीं वर्षा होने की भी संभावना दिख रही है। उधर मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात प्रदेश में सबसे कम नौ डिग्री सेल्सियस तापमान शहडोल में दर्ज किया गया। बुधवार को दिन का सबसे अधिक 33.1 डिग्री सेल्सियस तापमान खंडवा में रिकार्ड हुआ।

मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक भीषण चक्रवाती तूफान अकवान दक्षिण और उससे लगी पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में सक्रिय है। यह उत्तर, उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। 20 नवंबर की दोपहर तक इसके और तीव्र होते हुए मछलीपट्टनम और पुरी के बीच उत्तरी आंध्र प्रदेश, यनम और दक्षिणी ओडिशा के तटों को पार करने की संभावना है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के आसपास एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ द्रोणिका के रूप में बना हुआ है। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी वीएस यादव ने बताया कि अकवान के प्रभाव से गुरुवार से प्रदेश में बादल छाने लगेंगे। विशेषकर पूर्वी मध्य प्रदेश में बादल घने भी हो सकते हैं। हालांकि तूफान के अभी काफी दूर रहने के कारण उसके असर से वर्षा की संभावना अभी स्पष्ट नहीं है। मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि तूफान की मौजूदा स्थिति को देखते हुए गुरुवार से बादल छाने की संभावना तो बन ही रही है। साथ ही 21 एवं 22 नवंबर को रीवा, जबलपुर, शहडोल, भोपाल, नर्मदापुरम एवं इंदौर संभाग में कहीं-कहीं वर्षा होने का भी अनुमान है। उधर बादल छाने की वजह से गुरुवार से दिन के तापमान में कुछ गिरावट और रात के तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने के भी आसार हैं।



## नियमितीकरण की आस लगाए 4500 संविदा बिजली कर्मचारियों को झटका

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल:** मध्यप्रदेश में साढ़े चार हजार से अधिक संविदा बिजली कर्मचारियों के नियमित होने की उम्मीदों को झटका लगा है। ऊर्जा विभाग ने संविदा कर्मचारियों को समकक्ष नियमित पदों पर नवीन नियुक्ति देने के लिए योजना शुरू करने का आदेश जारी किया था, लेकिन अब सूचना के अधिकार के तहत विभाग ने ऐसी किसी योजना की जानकारी होने से ही इनकार कर दिया है।

ऊर्जा विभाग ने 24 जुलाई 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया था। योजना को तीन महीने के लिए लागू किया जाना था। इसके तहत संविदा कर्मचारियों को विभागीय परीक्षा के माध्यम से समकक्ष नियमित रिक्त पदों पर नियुक्ति देने की प्रक्रिया प्रस्तावित थी। कर्मचारी परीक्षा का इंतजार करते रहे, लेकिन 31 अक्टूबर की समय-सीमा तक न तो परीक्षा का कार्यक्रम जारी हुआ और न ही विज्ञापन निकाला गया।

ग्वालियर निवासी कोमल श्रीवास ने 24 अक्टूबर को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन देकर योजना के क्रियान्वयन की जानकारी मांगी थी। विभाग ने जवाब में कहा कि मांगी गई जानकारी उसके अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है।

**सरकारी स्कूलों की बदलेगी तस्वीर**

## भवन से लेकर प्रयोगशाला तक का होगा सर्वे

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल:** प्रदेश के शासकीय हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी दूर करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों में दर्ज विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में उपलब्ध सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करने को कहा है। इसमें स्कूल भवन, अतिरिक्त कक्ष, प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब और शौचालयों की जानकारी जुटाई जाएगी। अधिकारियों को यह सर्वे तीन दिन में पूरा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसके आधार पर भवनविहीन और अपर्याप्त अधोसंरचना वाले स्कूलों में आवश्यक निर्माण कार्यों की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए संचालनालय ने शासकीय हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में नए भवन, अतिरिक्त कक्ष, प्रयोगशाला कक्ष, कंप्यूटर लैब और शौचालय निर्माण सहित विभिन्न कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। इनमें भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान की प्रयोगशालाएं भी शामिल हैं। विभाग के अनुसार, सत्र 2022-23 से 2025-26 तक समग्र शिक्षा अभियान, पीएमश्री योजना और राज्य योजना के तहत भी निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई थी। इसके बावजूद कई स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

संचालनालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों को पूर्व में स्वीकृत निर्माण कार्यों की स्कूलवार सूची का परीक्षण करने और शेष जरूरतों की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं। यह जानकारी 19 नवंबर तक गूगल ड्राइव पर उपलब्ध करानी होगी। साथ ही निर्माण कार्यों की दोहराव से बचने के निर्देश भी दिए गए हैं।

**विद्योदय तीर्थ क्षेत्र में होगा लोकार्पण, आचार्य समयसागर ससंघ रहेंगे उपस्थित**

## आचार्य विद्यासागर पर 27 को जारी होंगे विशेष डाक टिकट

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल:** संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज के जीवन, कृतित्व और व्यक्तित्व पर केंद्रित विशेष डाक टिकट 27 नवंबर को जारी किए जाएंगे। हबीबगंज स्थित विद्योदय तीर्थ क्षेत्र में दोपहर को आयोजित समारोह में आचार्य समयसागर ससंघ का सानिध्य प्राप्त होगा।

आचार्य विद्यासागर महाराज ने राष्ट्र निर्माण, शिक्षा, संस्कृति और मानव कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जीवन भारतीय परंपरा, संस्कृत भाषा, चिकित्सा, हस्तशिल्प, स्वावलंबन और सामाजिक उत्थान के लिए समर्पित रहा। इस पहल के अंतर्गत विशेष डाक टिकटों के साथ आचार्यश्री के जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों को दर्शाने वाला मिनिएचर शीट सेट भी जारी किया जाएगा। इसमें उनकी मुनि दीक्षा, साधना और राष्ट्र एवं समाज के लिए किए गए कार्यों को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।



समारोह में प्रथम दिवस आवरण, हिंदी और अंग्रेजी में जीवन परिचय वाली विशेष विवरणिका तथा अन्य संग्रहणीय डाक सामग्री भी जारी की जाएगी। इस पहल में मध्यप्रदेश के एक सांसद एवं वर्तमान केंद्रीय मंत्री की विशेष भूमिका रही है। निर्यापक मुनि अभय सागर के विशेष प्रयासों से यह पहल साकार हो रही है।

**सेवा दूत** *विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास करेंगे पूर्णकालिक कार्यकर्ता*

## भाजपा का 1 से 25 दिसंबर तक चलेगा सेवा दूत अभियान

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल:** भाजपा प्रदेश में संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने के लिए 1 से 25 दिसंबर तक विशेष सेवा दूत अभियान चलाएगी। इसके तहत पूर्णकालिक कार्यकर्ता प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रवास करेंगे और स्थानीय स्तर पर संगठन की गतिविधियों, कार्यकर्ताओं की सक्रियता तथा जनसंपर्क कार्यों की समीक्षा करेंगे।

बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने प्रदेश पदाधिकारियों, संभाग प्रभारियों, जिला प्रभारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक को संबोधित किया। बैठक में हाल ही में संपन्न अभियानों की समीक्षा के साथ आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा और उनके क्रियान्वयन पर चर्चा हुई।



राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश ने कहा कि संगठन की मजबूती का आधार सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता हैं। पदाधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन गंभीरता से करना चाहिए। संगठन में संवाद, समन्वय और आपसी विश्वास बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने बूथ, मंडल, जिला और प्रदेश स्तर पर कार्यों की नियमित समीक्षा करने पर भी जोर दिया।

प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बताया कि सेवा दूत अभियान के दौरान पूर्णकालिक कार्यकर्ता विधानसभा क्षेत्रों में रहकर स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। इसका उद्देश्य बूथ स्तर तक संगठन की सक्रियता बढ़ाना और जनसंपर्क को प्रभावी बनाना है।

प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि संगठन के निर्धारित कार्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। इसके लिए जिला, मंडल और बूथ स्तर पर नियमित समीक्षा तथा कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है।

मेसर्स दैनिक नईदुनिया के लिए प्रकाशक अपूर्व तिवारी के द्वारा 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1,भोपाल-462011 से प्रकाशित एवं मुद्रक डॉ. विश्वास तिवारी के द्वारा नईदुनिया प. प्रा.लि., 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1, भोपाल-462011 से मुद्रित। प्रबंध संपादक: डॉ. सुरेन्द्र तिवारी एवं संपादक: अपूर्व तिवारी। *
फोन-0755-2550900-01, e-mail : naidunia@gmail.com ( * समाचार पत्र से संबंधित सभी प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र सिर्फ भोपाल होगा।) आर.एन.आई. रजि. क्र. 47694/88, www.naiduniaonline.com